

वायुसेना उप प्रमुख बोले- राफेल एक बेहतरीन विमान, इसे उड़ाने को सेना तैयार



नेशनल डेस्क।

राफेल से जुड़े 58,000 करोड़ रुपये के सौदे को लेकर विवाद के बीच वायुसेना ने कहा कि यह एक बेहतरीन विमान है जो भारत को अभूतपूर्व युद्धक क्षमता प्रदान करेगा। वायुसेना के उप प्रमुख (वाइस चीफ

ऑफ एयर स्टाफ) एयर मार्शल एस बी देव ने कहा कि राफेल सौदे की आलोचना करने वाले लोगों को निर्धारित मानदंडों और खरीद प्रक्रिया को समझना चाहिए। देव ने कहा कि राफेल एक बेहतरीन विमान है...यह काफी सक्षम विमान है और हम इसे उड़ाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

राफेल विवाद से जुड़े विवाद के बारे में उनसे एक कार्यक्रम से इतर सवाल किय गया था। एयर मार्शल ने कहा कि राफेल विमान से भारत को इस क्षेत्र में अपने प्रतिद्वंद्वियों पर अभूतपूर्व बढ़त प्राप्त होगी। भारत ने 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए 58,000 करोड़ रुपये की

लागत से सितंबर 2016 में फ्रांस के साथ अंतर-सरकारी समझौता किया था। इन विमानों की आपूर्ति सितंबर 2019 से शुरू होने वाली है। काग्रेस ने इस सौदे को लेकर कई सवाल उठाए हैं जिनमें विमान की कीमतें शामिल हैं। हालांकि सरकार ने आरोपों को खारिज कर दिया है।

लड़की के अपहरण वाले बयान की मनसे-राकांपा ने की आलोचना

मुंबई।

मनसे और राकांपा ने महाराष्ट्र भाजपा विधायक राम कदम की तुलना बुधवार को रावण से की जिन्होंने युवाओं से कथित रूप से कहा था कि उनकी पसंद की लड़की अगर उनका प्रस्ताव ठुकरा भी देती तो भी वह उसका 'अपहरण' कर लेते। घाटकोपर विधायक अपनी टिप्पणी को लेकर खेद जता चुके हैं। उन्होंने उक्त टिप्पणी अपने घाटकोपर

विधानसभा क्षेत्र में सोमवार की रात में आयोजित एक 'दही हांडी' कार्यक्रम में की थी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने घाटकोपर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के आवास के बाहर पोस्टर लगाए हैं जिसमें कदम को रावण के तौर पर दिखाया गया है। राज ठाकरे नीत पार्टी ने पोस्टर में लिखा है कि विधायक बेटियों का अपहरण करेंगे। यदि वह या उनके लोग ऐसा करते हैं तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराइये और हमें बताइये। हम

आपकी बेटियों की सुरक्षा में आपकी मदद करेंगे।' राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नवाब मलिक ने कहा कि भाजपा का 'रावण' जैसा चेहरा सामने आ गया है और उसके विधायक जब तक माफी नहीं मांगते उन्हें 'रावण कदम' कहा जाएगा। उन्होंने कहा, 'खेद जताना और माफी मांगना अलग अलग चीजें हैं। राकांपा उनके खिलाफ प्रदर्शन और उन्हें 'रावण कदम' कहना बाद तक जारी रखेगी जब तक वह माफी

नहीं मांगते। उनके माफी मांगने तक पूरे राज्य में प्रदर्शन किये जाएंगे।' कदम एक वीडियो क्लिप में उक्त टिप्पणी करते हुए सुने गए थे। उन्होंने कहा कि उनकी टिप्पणी से छेड़छाड़ की गई है। उन्होंने देर मंगलवार को कहा कि मैंने भीड़ में खड़े एक व्यक्ति की पंक्ति को केवल दोहराया था वह मेरी पंक्ति नहीं थी। क्लिप मात्र 40 सेकंड में वायरल हो गई। यद्यपि मैंने बाद में कहा था कि सभी घरों में माताएं, बहनें और बेटियां लक्ष्मी हैं।

कांग्रेस ने साधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना, शेयर किया पुराना वीडियो

नई दिल्ली।

कांग्रेस ने डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत में लगातार गिरावट और पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने को लेकर आज सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने वादों



में विफल रहे हैं। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी के भाषण का एक पुराना वीडियो शेयर करते हुए कहा, 'रुपया 72 पर पहुंच गया। पेट्रोल-डीजल की कीमत अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। मोदी जी ने जो बातें की थीं उसमें वह विफल रहे।' दरअसल, शुक्रआती कारोबार में सुधार के लक्षण दिखाते के बाद बुधवार को भी रुपये में जल्द ही गिरावट देखी गई। डॉलर के मुकाबले यह 21 पैसे टूटकर 71.79 पर पहुंच गया। मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपया 37 पैसे टूटकर 71.58 पर बंद हुआ था।

पुंछ में सेना के जवान की हत्या के सिलसिले में एक महिला सहित दो गिरफ्तार



अलयास और जैनब बी को कल मेंडेर से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि सेना की "डिफेंस सर्विस कर्पोर" (डीएससी) यूनिट का जवान मोहम्मद मतलूब पांच मई को छजीला गांव में हाथापाई के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गया था। मतलूब ने 19 मई को अस्पताल में दम तोड़ दिया था। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि पुंछ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजीव पांडेय ने फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए सहायक पुलिस अधीक्षक अनवार-उल हक की निगरानी में एक विशेष जांच दल गठित किया था। उन्होंने बताया कि आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है।

जम्मू। जम्मू के एक गांव में जमीन को लेकर हाथापाई के दौरान सेना के एक जवान के मारे जाने के करीब चार माह बाद पुलिस ने इस मामले में एक महिला सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बुधवार को बताया कि मोहम्मद अलयास और जैनब बी को कल मेंडेर से गिरफ्तार किया गया। उन्होंने बताया कि सेना की "डिफेंस सर्विस कर्पोर" (डीएससी) यूनिट का जवान मोहम्मद मतलूब पांच मई को छजीला गांव में हाथापाई के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गया था। मतलूब ने 19 मई को अस्पताल में दम तोड़ दिया था। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि पुंछ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजीव पांडेय ने फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए सहायक पुलिस अधीक्षक अनवार-उल हक की निगरानी में एक विशेष जांच दल गठित किया था। उन्होंने बताया कि आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है।

मलयालम उपन्यास 'मीशा' होगी प्रकाशित, उच्चतम न्यायालय ने बैन लगाने से किया इंकार

नेशनल डेस्क।

उच्चतम न्यायालय ने लेखक एस हरीश के मलयालम उपन्यास 'मीशा' को प्रतिबंधित करने से बुधवार को इन्कार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता एन राधाकृष्णन की याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि किसी लेखक की कल्पना पर रोक नहीं लगायी जा सकती। लेखक की कल्पना को संरक्षण

मिलना चाहिए। न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि संविधान में साफ स्पष्ट है कि किसी भी शख्स को अपने विचारों को रखने का अधिकार है। एक लेखक अपने चारों तरफ के वातावरण को देखता है, उसे अनुभव करता है और अपनी कल्पना को शब्दों के जरिये बयां करता है। आप किसी शख्स का विरोध तो कर सकते हैं लेकिन आपको उसे गलत ठहराने के लिए तार्किक आधार पर अपनी बात कहनी होगी। उल्लेखनीय है कि मलयालम लेखक एस हरीश के

उपन्यास पर कुछ हिंदुवादी संगठनों को ऐतराज था। उपन्यास मीशा के कुछ अंश सोशल मीडिया में वायरल हो गए थे। जुलाई के दौरान 'मीशा' के तीन अध्याय मलयालम साप्ताहिक मातृभूमि में प्रकाशित हुए थे। लेकिन इसके बाद एस हरीश को हिंदुवादी संगठनों की धमकियां मिलने लगीं और उन्होंने 21 जुलाई को अपना



उपन्यास वापस ले लिया। हालांकि इस फैसले के बाद केरल के मुख्यमंत्री पिनारayi विजयन सहित राज्य के कई जाने-माने लेखक उनके समर्थन में आए थे।

दक्षिण कश्मीर में ट्रेन सेवाएं फिर से बहाल

श्रीनगर।

दक्षिण कश्मीर में सुरक्षा कार्यों से मंगलवार को स्थगित की गयीं ट्रेन सेवाएं बुधवार को फिर से बहाल कर दी गयीं। दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकवादियों के खिलाफ सोमवार को व्यापक तलाश अभियान को बाधित करने का प्रयास कर रहे प्रदर्शनकारियों को

तितर-बितर करने के सुरक्षा बलों को गोलियों चलाती पड़ोी थीं जिसमें एक युवक की मौत हो गयी थी। इसके बाद सुरक्षा कार्यों से ट्रेन सेवाएं बंद कर दी गयी थीं। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आज यहां बताया कि पुलिस की ओर से मिले ताजे मशरिफ के बाद दक्षिण कश्मीर में सभी ट्रेनों का परिचालन बहाल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि मध्य कश्मीर

के बडगाम.श्रीनगर से दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग-काजीगुंड तथा जम्मू क्षेत्र के बनिहाल के बीच सभी ट्रेनें निर्धारित समय पर चलेगी। इस मार्ग पर भारी भीड़ होती है क्योंकि जम्मू की ओर यात्रा करने वाले अधिकांश लोग बनिहाल तक जाना पसंद करते हैं। उत्तरी कश्मीर में पूर्व निर्धारित समय के हिसाब से सभी ट्रेनें चल रही हैं।

श्रीनगर।

नैशनल कान्फेंस ने एक बड़ा फैसला लेते हुये अक्तूबर से होने वाले निकाय एवं पंचायती चुनावों में भाग नहीं लेने का फैसला किया है। इस बारे में पार्टी के प्रचार और श्रीनगर से सांसद डा फारूक अब्दुल्ला ने स्वयं पत्रकारों को बताया। डा अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर में चुनाव के लिए माहौल उचित नहीं है। पार्टी चुनावों में भाग



नहीं लेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी की कार्यगुप की बैठक में यह फैसला किया गया है कि पार्टी चुनावों से परे रहेगी। नैका का कोई उम्मीदवार चुनाव में खड़ा नहीं होगा। गौरतलब है कि कश्मीर घाटी में आतंकियों और अलगाववादियों ने चुनावों के बहिष्कार का अहवाल किया है।

2016 में संसदीय चुनावों में भी कश्मीर में काफी हिंसा देखने को मिली थी।

तरुण विजय के द्वाीट ने मचाया हड़कंप, प्रधानमंत्री का किया विरोध

नेशनल डेस्क।

मंगलवार रात सोशल मीडिया पर उस हड़कंप मच गया जब भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद तरुण विजय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ट्वीट किया। यही नहीं उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के पक्ष में भी ट्वीट किए। मामला सामने आने के बाद सभी ट्वीट्स डिलीट कर दिये गये। विजय ने अकाउंट हैक होने का दावा किया और सफाई दी कि वह एवं उनका परिवार श्री मोदी एवं भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के लिए प्राण न्यौछावर कर देंगे। विजय ने अपने ट्वीट में उनके प्रति विश्वास प्रकट करने वाले और गलत ट्वीटों पर विश्वास नहीं करने के लिए अपने शुभचिंतकों को धन्यवाद दिया। उन्होंने सफाई दी

कि उनके हैंडल से गलत ट्वीट तब हुए जब वह मकान बदल रहे थे। उनके पासवर्ड का दुरुपयोग किया गया और वह इसके लिए पुलिस में शिकायत दर्ज करा रहे हैं। उन्होंने पासवर्ड बदलने की भी जानकारी दी। एक टेलीविजन चैनल की रिपोर्ट के अनुसार विजय ने कहा कि हम प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा अध्यक्ष शाह के लिए ही जीएंगे और मरेंगे। वे हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी हैं। मैं और मेरा परिवार भाजपा के लिए दिन रात काम करेंगा। मेरा परिवार भाजपा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देगा। यह 2019 के पहले की साजिश है। कृपया मुझे भाजपा विरोधी तत्वों से बचाइये। इससे पहले विजय के ट्विटर हैंडल से पीएम

मोदी के खिलाफ और कांग्रेस अध्यक्ष के पक्ष में लगातार कई ट्वीट किए गए। हालांकि, बाद में उन्होंने अपने ये ट्वीट मिटा दिए। सबसे पहले राहुल गांधी की कैलाश मानसरोवर यात्रा के पक्ष में ट्वीट किया गया जिसमें लिखा गया कि जो लोग कैलाश यात्रा का मजाक उड़ा रहे हैं, ऐसा एक दुश्मन को नहीं करना चाहिए। ये जो भी है राहुल और शिव के बीच में है, शिव से बड़ा कुछ भी नहीं है। मैं खुद तीन बार कैलाश जा चुका हूं। इसके बाद दूसरा ट्वीट प्रधानमंत्री को लेकर आया जिसमें कहा गया कि हैलो, तुम इसलिए वहां पर नहीं हो क्योंकि तुम लोकप्रिय हो। तुम इसलिए वहां हो, क्योंकि लोग तुम्हारे पीछे हैं। अपने घमंड को दूर करो, हे भगवान, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम लोकप्रिय

हो। इन ट्वीट्स के बाद विजय को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाने लगा जिसके बाद उन्होंने ट्वीट किया, वह अभी मॉर्निंग वॉक पर हैं, जो व्यक्ति उनका टि्वटर अकाउंट हैंडल करता था, उसे उन्होंने हटा दिया है। विजय के इन ट्वीट्स के बाद कांग्रेस नेताओं ने भी उनपर टिप्पणियां कीं। कांग्रेस के संचार विभाग के प्रमुख रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि तरुण विजय जी, हैसला अपना बुलंद कर लीजिये। निर्भय होकर सच्चाई के साथ चलीये, राहुल गांधी जी की कैलाश यात्रा के लिए आपने जो कुछ लिखा, अपने हुक्मरानों के डर से उसे मिटाइये नहीं, सत्यम, शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है। महादेव आपको सत्य का रास्ता दिखाते रहेंगे व असत्य का नाश होगा।

गुटखा घोटाले में बड़ी कार्रवाई, सीबीआई ने तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री व के घर मारे छापे

नेशनल डेस्क।

तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री और पुलिस महानिदेशक के आवासों समेत राज्य में करीब 40 स्थानों पर सीबीआई ने गुटखा घोटाले के संबंध में बुधवार को छापेमारी की। अधिकारियों ने बताया कि पूरे राज्य में तलाशियां जारी हैं। लेकिन अधिकारी ने इस बात की पुष्टि नहीं की गई कि किन स्थानों पर छापेमारी हुई है। उनका कहना है कि इससे अभियान प्रभावित हो सकता है। अधिकारियों ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्री सी विजयभास्कर और डीजीपी टीके राजेंद्रन के आवासों के साथ ही एक पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तथा अन्य के घरों पर तलाशी ली जा रही है। इस घोटाले का खुलासा आठ जुलाई, 2017 को उस समय हुआ था जब आयकर विभाग के अधिकारियों ने तमिलनाडु में पान मसाला और गुटखा उत्पादकों के गोदामों, कार्यालयों और आवासों पर छापे मारे थे। गुटखा उत्पादकों पर 250 करोड़ रुपये की आयकर चोरी के आरोप हैं। तमिलनाडु सरकार ने 2013 में गुटखा और पान मसाला समेत चबाने वाले तंबाकू के विभिन्न प्रकारों के उत्पादन, भंडारण और बिक्री पर रोक लगा दी थी। छापेमारी के दौरान विभाग ने एक डायरी जब्त की थी जिसमें उन लोगों के नाम लिखे हुए थे जिन्हें गुटखा उत्पादकों ने कथित तौर पर रिश्त द दी थी। द्रमुक के एक नेता की याचिका पर इस साल अप्रैल में मद्रास उच्च न्यायालय ने सीबीआई को यह मामला सौंप दिया था।



संक्षिप्त समाचार



देश का पहला रोटी बैक, मुपत में मिलेगा खाना

डूंगरपुर। दक्षिणी राजस्थान के छोटे शहर डूंगरपुर में देश का पहला रोटी बैक खोला गया है जहां कोई भी व्यक्ति निःशुल्क दोपहर का भोजन कर सकता है। शहर में अपनी तरह की यह अनोखी पहल नगर परिषद के अस्पताल में की गई है। इसके लिए डूंगरपुर नगर परिषद ने स्थान उपलब्ध कराया है जबकि दिन-प्रतिदिन की व्यवस्था का जिम्मा शहर के समाजसेवियों ने उठाया है। नगर परिषद के सभापति एवं स्वच्छ राजस्थान के ब्रांड एम्बेसडर के.के.गुप्ता की पहल पर यह रोटी बैक खोलने का निर्णय लिया है। पिछले सप्ताह इस बैक खोलने की घोषणा की गई थी। गुप्ता ने बताया कि शहर में इस जिले का एकमात्र अस्पताल है। मरीजों को तो भोजन अस्पताल उपलब्ध करा देता है लेकिन उनके तैमारदारों को भोजन के लिए परेशान होना पड़ता है। शहर में पर्याप्त होटल या धर्मशाला भी उपलब्ध नहीं है। आस-पास के क्षेत्रों में इस शहर का प्रमुख स्थान है। यहां सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। परीक्षार्थियों को रहने और खाने की भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखकर रोटी बैक की शुरूआत की गई है। उन्होंने बताया कि इस बैक से कोई भी व्यक्ति निःशुल्क रोटी प्राप्त कर सकता है। कोई व्यक्ति चाहे तो धन या श्रम का दान भी कर सकता है। उन्होंने कहा कि रोटी बैक के संचालन के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना की गई है। कोई भी व्यक्ति एक लाख रुपए दान करके इसका ट्रस्टी बन सकता है। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति विशेष अवसरों जैसे जन्मदिवस, जयंती या पुण्यतिथि तथा त्योहारों पर भोजन की व्यवस्था का जिम्मा ले सकता है। गुप्ता ने बताया कि इसमें बच्चों को जोड़ने के लिए एक विशेष व्यवस्था शुरू की गई है। स्कूल में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे से घर से एक अतिरिक्त रोटी लाने के लिए कहा जाएगा। इन रोटियों को लंच के समय जरूरतमंद व्यक्तियों तक पहुंचा दिया जाएगा।

चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी में छोड़ा पानी, एयरलिफ्ट कर अरुणाचल प्रदेश में 19 लोगों को बचाया

शिलांग। चीन में भारी बारिश के चलते पिछले दिनों ब्रह्मपुत्र नदी में पानी छोड़ दिया है। चीन के पानी छोड़ने से अरुणाचल प्रदेश की सियांग नदी में भी पानी बढ़ रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार त्संगपो नदी से 9020 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। वहीं अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित एक द्वीप में फंसे 19 लोगों को वायुसेना ने हवाई मार्ग से सुरक्षित बाहर निकाल लिया जबकि असम के धेमाजी जिले से 200 से अधिक लोगों को बचाया गया। अधिकारियों ने बताया कि भारी बारिश के कारण धेमाजी में सियांग नदी उफान पर है। सियांग नदी चीन से निकलती है। मेघालय के तीन जिलों में भी बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। सियांग नदी मूल रूप से तिब्बत से निकलती है और चीन में इसे त्संगपो के रूप में जाना जाता है। यह लोहित और दिबांग नदी के साथ मिलकर असम में ब्रह्मपुत्र नदी में तब्दील हो जाती है।

मालेगांव धमाका एनआईए ने पुरोहित सहित आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया टाली

मुंबई। एक स्थानीय अदालत ने बुधवार को 2008 के मालेगांव धमाका मामले में लैफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने की प्रक्रिया टाल दी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत के न्यायाधीश विनोद पाडलकर ने आरोप तय करने का काम उस वक टाल दिया जब पुरोहित एवं अन्य आरोपियों ने गैर-कानूनी गतिविधियां रोकथाम कानून (यूपपीए) के तहत उन पर मुकदमा चलाने की वैधता पर आपत्ति जताई। पूर्व मेजर रमेश उपाध्याय नाम के एक आरोपी ने दलील दी कि मुकदमे की सुनवाई शुरू करने से पहले इस पर फैसला होना चाहिए कि क्या उन पर यूपपीए लागू हो सकता है। न्यायाधीश ने मामले को स्थगित कर दिया और कहा कि अदालत अगले सोमवार से सभी आरोपियों की दलीलें सुनेगी। उन्होंने कहा कि दलीलों की सुनवाई हर रोज होगी और इसकी शुरुआत पुरोहित से होगी। बंबई उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पुरोहित की वह अर्जी खारिज कर दी थी जिसमें उन्होंने मांग की थी कि निचली अदालत को इस मामले में उनके और अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने से रोका जाए। पुरोहित ने अपनी अर्जी में उच्च न्यायालय से अनुरोध किया था कि आरोप तय करने की प्रक्रिया पर तब तक रोक लगाई जाए जब तक उच्च न्यायालय द्वारा उन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी के मुद्दे पर फैसला नहीं कर लेता। पिछले साल 18 दिसंबर को उच्च न्यायालय ने पुरोहित पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार की मंजूरी को रद्द करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने उच्चतम न्यायालय का रुख किया था, जिसने 20 अप्रैल को इस मामले में दखल से इनकार कर दिया था।

पुलिस के उत्साह को कम करने वाले लेखों से बचे मीडिया: वैद

श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक डॉ. एस. पी. वैद ने कहा है कि मीडिया को राज्य में दशकों से युद्ध लड़ रही पुलिस के उत्साह को कम करने वाले लेखों को प्रकाशित करने से बचना चाहिए। वैद ने राज्य के पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण पर समाचार चैनल एनडीटीवी की रिपोर्ट पर यह प्रतिक्रिया व्यक्त की। वैद ने ट्वीट किया, जम्मू कश्मीर पुलिस दशकों से छ्थ युद्ध लड़ रही है। इस कार्य के लिए बहुत साहस और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। ऐसे में पुलिस के उत्साह को कम करने वाले कल्पित लेखों से बचना चाहिए। मैं एनडीटीवी की रिपोर्ट के संबंध में कहना चाहता हूं कि स्थानांतरण सरकार का विशेषाधिकार और एक नियमित प्रक्रिया है। एनडीटीवी की रिपोर्ट में कहा गया था कि गृह मंत्रालय जम्मू कश्मीर पुलिस के कामकाज से संतुष्ट नहीं है और वह वैद के विकल्प की तलाश कर रहा है। गृह मंत्रालय ने हालांकि सभी आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा है कि वह जम्मू कश्मीर पुलिस सराहनीय कार्य कर रही है। गृह मंत्रालय ने कई अवसरों पर राज्य पुलिस के कामकाज की सराहना की है।



संपादकीय

मीड़ की हिंसा पर रोक

भीड़ की हिंसा पर रोक लगाने के उपाय सुझाने वाली सचिवों की एक समिति की रपट पर विचार करने के दौरान यदि वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री इस नतीजे पर पहुंचे कि गवाहों की सुरक्षा का कानून बनाया जाना चाहिए तो फिर यह काम प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए। यह इसलिए आवश्यक है, क्योंकि भीड़ की हिंसा के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। ये मामले न केवल कानून एवं व्यवस्था के समक्ष चुनौती खड़ी कर रहे हैं, बल्कि देश की बदनामी भी करा रहे हैं। गत दिवस ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्मादी भीड़ की हिंसा के एक मामले की सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि इस घटना की जांच मेरट के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की देखरेख में की जाए। भीड़ की हिंसा के बढ़ते मामले कहीं न कहीं कानून हाथ में लेने की प्रवृति को रेखांकित कर रहे हैं। ऐसे मामलों में आम तौर पर संदिग्ध बच्चा चोरों और पशु चोरों को निशाना बनाया जा रहा है। कई बार अन्य संदिग्ध लोग भी उन्मादी भीड़ का शिकार बन जाते हैं। इनमें कई तो संदिग्ध भी नहीं होते, लेकिन किसी कारण संदेह के दायरे में आ जाते हैं या फिर किसी अफवाह का शिकार हो जाते हैं। ऐसी अफवाहें फैलाने में सोशल मीडिया और खासकर वाट्सएप की भूमिका रहती है। इन कंपनियों का यह दायित्व है कि वे अफवाहों पर रोक लगाने को लेकर गंभीरता दिखाएं। यह ठीक नहीं कि इस मामले में सोशल मीडिया कंपनियां आनाकानी ही करती दिख रही हैं। ऐसी कंपनियों को जवाबदेही के दायरे में लाया जाना चाहिए, लेकिन यह भी ध्यान रहे कि केवल इतने से बात नहीं बनेगी। इसी तरह इसमें भी संदेह है कि केवल गवाहों की सुरक्षा का कानून बन जाने से उन्मादी भीड़ की हिंसा के मामले थमेंगे। 1यह सही है कि गवाहों की सुरक्षा देने वाले किसी कानून का निर्माण समय की मांग है, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि भीड़ की हिंसा वाली घटनाओं में शामिल तत्व आम तौर पर कानून से भय ही नहीं खाते। यह भी किसी से छिपा नहीं कि इस तरह के मामलों की जांच और सुनवाई में लंबा समय लगता है। बीते एक साल में भीड़ की हिंसा के करीब 40 मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन शायद ही किसी में आरोपित को सजा सुनाई गई हो। बेहतर हो कि सचिवों की समिति की ओर से तैयार की गई रपट पर विचार कर रही वरिष्ठ मंत्रियों की समिति यह समझे कि भीड़ की हिंसा के मामलो का त्वरित निस्तारण ही इस तरह की घटनाओं की रोकथाम में प्रभावी सिद्ध होगा। किसी कारण किसी निदरेष या फिर संदिग्ध शख्स के प्रति भीड़ की हिंसा सभ्य समाज को शर्मिंदा करती है। निःसंदेह जहां कहीं भी कानूनों में कमी या फिर विसंगति हो तो उसे दूर किया जाना चाहिए, लेकिन यह ध्यान रहे तो बेहतर कि सक्षम कानून तभी असर दिखाते हैं जब उनके अमल की इच्छाशक्ति भी प्रदर्शित की जाती है। स्पष्ट है कि केंद्रीय मंत्रियों की समिति का मूल उद्देश्य एक और कानून बनाना ही नहीं, बल्कि उस पर प्रभावी तरीके से अमल की राह खोजना भी होना चाहिए।

संपादकीय

बड़ी कठिन है डगर..

पाकिस्तान/ आशीष शुक्ला

पाकिस्तान में 25 जुलाई को हुए आम चुनाव के परिणाम कई कारणों से महत्वपूर्ण हैं। अरसे बाद देश के लोकतांत्रिक पटल पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पी.टी.आई.) नामक नई राजनीतिक ताकत का उदय हुआ है। पहली बार मतदान करने वाले युवा मतदाताओं को पाकिस्तान में सैन्य शासन का कोई व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, और अपने आप में यह किसी उपलब्धि से कम नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के पास इन उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए थोड़ा भी समय नहीं है। इसलिए कि पाकिस्तान के समक्ष चुनौतियों की लंबी फेहरिस्त है, जो बेहद मुश्किल हैं। जहां तक आंतरिक राजनीतिक स्थिरता का प्रश्न है, तो 342 सदस्यों वाली नेशनल असेंबली में पीटीआई के151 सदस्य हैं। सरकार रखनी है, तो उसे 21 अन्य सदस्यों की कमी पूरी करने के लिए कुछ छोटे दलों और अन्य निर्दलीय सदस्यों पर निर्भर रहना है। विपक्षी दलों विशेषकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के बीच एकजुटता की भारी कमी के कारण शायद ही पीटीआई सरकार को कोई समस्या होने वाली है। लेकिन यदि किसी भी मौके पर पीएमएल-एन, पीपीपी, मुल्हिदा मजलिस-ए-अमल (एमएमए)-जिनके पास कुल 150 सदस्य हैं-और कुछ अन्य छोटे-मोटे दल अपने मतभेदों को भुलाकर साथ आ जाएं तो पीटीआई के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। इनके अतिरिक्त भी कुछ अन्य बड़े सवाल हैं, जिनका जवाब जल्द से जल्द ढूंढ़ लिया जाना चाहिए। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बड़े संकट की ओर बढ़ रही है। चाहे लगातार बढ़ता वित्तीय घाटा हो, लगातार कम हो रहा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो, या डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपये की गिर रही कीमत, आंकड़े भयावह तस्वीर पेश कर रहे हैं। इन स्थितियों के मद्देनजर चीन ने हाल में पाकिस्तान को दो बिलियन डॉलर के लोन देने की न केवल घोषणा की, बल्कि एक बिलियन से अधिक की राशि आनन-फानन में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान (पाकिस्तानी रिजर्व बैंक) को हस्तांतरित भी कर दी। लेकिन इसके बावजूद उसे आईएमएफ की शरण में जाना ही पड़ेगा। ट्रंप प्रशासन के लगातार कड़े होते रु ख से यह रास्ता भी कतई आसान नहीं रहने वाला है। अमेरिका पहले ही स्पष्ट कर चुका है कि वह पाकिस्तान को आईएमएफ द्वारा ऐसे किसी भी बेलआउट का विरोध करेगा जिसका उपयोग चीन को फायदा पहुंचाने में हो। इस चुनाव में इमरान खान पाकिस्तानी सेना के चहेते बनकर उभरे हैं। कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सेना उन्हें ही प्रधानमंत्री के पद पर देखना चाहती थी। विपक्षी दलों का यह आरोप भी है कि सेना ने इमरान खान की पार्टी को चुनाव पूर्व, चुनाव के दौरान और चुनाव के उपरान्त काफी मदद की। अब चूंकि इमरान खान सत्ता के शीर्ष पर पहुंच चुके हैं, ऐसी स्थिति में उनके सामने ऐसी नीति अपनाने की चुनौती है, जिससे उनके और सेना के बीच किसी तरह का मतभेद सामने न आए। वह पाकिस्तानी लोगों के सामने सेना द्वारा नियंत्रित होते हुए न प्रतीत हों वैसे तो किसी देश की विदेश नीति उस देश के राष्ट्रीय हितों को हासिल करने का जरिया होती है, लेकिन पाकिस्तान जैसे देश में वह एक संस्था विशेष की बपौती बन गई है। ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तान की सेना ने पाकिस्तान की विदेश नीति के महत्वपूर्ण भागों को न केवल प्रभावित किया है, बल्कि अक्सर नियंत्रित भी किया है। पाकिस्तान की नई सरकार के सामने विदेश नीति पर

अमेरिका, पाकिस्तान और चीन के बीच बढ़ती नजदीकियों को संदेह की दृष्टि से देखता है। पाकिस्तान अच्छे से जानता है कि अमेरिका जैसे देश को लंबे समय तक नाखुश रखना उसके लिए परेशानियों का सबब बन सकता है, लेकिन वह चीन से बढ़ती प्रगाढ़ता में भी कोई कमी नहीं करना चाहता। दोनों काम एक साथ करने का मतलब है तलवार की धार पर चलना। जहां तक दक्षिण एशिया का सवाल है, तो पाकिस्तान के अपने पश्चिमी और पूर्वी पड़ोसियों से अच्छे संबंध नहीं हैं। तमाम नियंतण उपायों के बावजूद अफगानिस्तान में हिंसा खत्म होने का नाम नहीं ले रही।

नई छाप छोड़ने की चुनौती है। वह कितना सफल होगी, यह तो समय के गर्भ में है। यहां वर्तमान समय में विदेश नीति के संदर्भ में उपस्थित और भावी चुनौतियों का जिक्र करना उपयुक्त होगा। नियंतण पटल पर लगातार बदल रही भू-राजनीतिक और भू-रणनीतिक स्थितियों ने पाकिस्तान के समक्ष चुनौतियों का पहाड़ खड़ा कर दिया है। एक तरफ तो आतंकवाद को समर्थन देने और उसके विरु ढ्ढ प्रभावी कार्रवाई न करने के कारण अंतरराष्ट्रीय मंचों पर अलग-थलग पड़ने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ अमेरिका से द्विपक्षीय संबंधों में लगातार आ रही गिरावट नई परेशानी का सबब है। पिछले महीने माइक पोम्पियो, अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और इमरान खान के बीच टेलीफोन वार्ता हुई जिसमें उन्होंने आतंकवाद के मुद्दे पर कार्रवाई की मांग की थी। इसके बाद, बीते एक सितम्बर को पेंटागन ने पाकिस्तान को 300 मिलियन डॉलर की सहायता यह कहते हुए राशि रोक दी कि वह पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठनों, जिनमें हक़ानी नेटवर्क और लश्कर-ए-तैयबा शामिल हैं, के खिलाफ बिना भेदभाव के कार्रवाई नहीं कर रहा है। वाशिंगटन ने यह भी स्पष्ट किया है कि पाकिस्तान अच्छे रिश्ते चाहता है, तो उसे अफगानिस्तान में अमेरिकी रणनीति का समर्थन करना ही होगा। इसी ऋम में माइक पोम्पियो का हालिया दक्षिण एशिया दौरा बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, जिस दौरान वह पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर आड़े हाथों लेंगे। अमेरिका, पाकिस्तान और चीन के बीच बढ़ती नजदीकियों को संदेह की दृष्टि से देखता है। पाकिस्तान अच्छे से जानता है कि अमेरिका जैसे देश को लंबे समय तक नाखुश रखना उसके लिए परेशानियों का सबब बन सकता है, लेकिन वह चीन से बढ़ती प्रगाढ़ता में भी कोई कमी नहीं करना चाहता। दोनों काम एक साथ करने का मतलब है तलवार की धार पर चलना। जहां तक दक्षिण एशिया का सवाल है, तो पाकिस्तान के अपने पश्चिमी और पूर्वी पड़ोसियों से अच्छे संबंध नहीं हैं। तमाम नियंतण उपायों के बावजूद अफगानिस्तान में हिंसा खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बहुत से विश्लेषकों का मानना है कि जब तक पाकिस्तान, अफगानिस्तान के प्रति नीति में बदलाव नहीं करेगा और आतंकी संगठनों को प्रश्रय देना बंद नहीं करेगा, तब तक अफ़गानिस्तान में शांति की



वस्तु एवं सेवा शुल्क उपकर उपहार से कम नहीं

ए के भट्टाचार्य

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 23 अगस्त को फिर से वित्त मंत्रालय का कामकाज संभाल लिया। बड़े ऑपरेशन के कारण वह तीन महीने तक नॉर्थ ब्लॉक के कामकाज से दूर रहे। किसी सरकार के कार्यकाल में तीन महीने का समय भले ही मामूली अवधि हो लेकिन जेटली के लिए यह लंबा समय लगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के व्यापक आर्थिक सिद्धांतों में उल्लेखनीय बदलाव आए हैं। इनसे नई चुनौतियां और कुछ नए अवसर भी उभरे हैं। अप्रैल के अंत में तेल की कीमतें (भारतीय बारकेट) प्रति बैरल 70 डॉलर के आसपास थीं। आज इसमें छह फीसदी उछाल आ चुकी है और यह 74 डॉलर प्रति बैरल के आसपास है। पिछले तीन महीने में भारतीय रुपये की विनिमय दर में चार फीसदी से अधिक की कमी आई है। मई में रुपया डॉलर के मुकाबले 68 के स्तर पर था और अब 71 पर पहुंच चुका है। मई तक निर्यात में तेजी आनी शुरू हो गई थी। निर्यात लगातार बढ़ रहा है लेकिन अब आयात भी तेजी से बढ़ने लगा है जिसके कारण जुलाई में व्यापार घाटा पांच साल के रिकॉर्ड स्तर 18 अरब डॉलर तक पहुंच गया था। कुछ आकलनों के मुताबिक इस साल चालू खाते का घाटा तीन फीसदी के स्तर तक पहुंच सकता है। वर्ष 2017-18 में यह सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 1.9 फीसदी रहा था। ये सभी क्षेत्र जेटली के समक्ष नीतिगत मुश्किलें पैदा करेंगे। उन पर डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरावट को थामने और आयात शुल्क बढ़ाने का दबाव होगा। अगर वह इस तरह के दबाव के आगे झुकते हैं तो इसके प्रतिकूल परिणाम होंगे जो अर्थव्यवस्था के लिए और बड़ी मुश्किलें पैदा करेंगे। न तो मजबूत रुपया और न ही संरक्षणवादी उपाय भारतीय निर्यात को पटरी पर ला सकते हैं अथवा भुगतान संतुलन को दुरुस्त कर सकते हैं। बाद में निर्यात की जाने वाली

आयातित वस्तुओं के मूल्य संवर्द्धन से घरेलू विनिर्माण को होने वाले संभावित नुकसान को ध्यान में रखते हुए सरकार को आयात शुल्क बढ़ाने के प्रलोभन से बचना चाहिए। रुपये की गिरावट से निर्यात में मदद मिलेगी लेकिन जेटली को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि बाजार में अस्थिरता की स्थिति पैदा किए बिना इसका इंतजान किया जाना चाहिए और साथ ही देश में निर्यात के बुनियादी ढांचे को सुधारने के लिए पर्याप्त उपाय किए जाने चाहिए। तेल के मोर्चे पर जेटली के पास और भी सीमित विकल्प होंगे क्योंकि ईरान से आपूर्ति बाधित होने से अनिश्चितता और गहरा रही है। यह चुनावी वर्ष है। कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से सरकार पर उर्वरकों और पेट्रोलियम पदार्थों की सब्सिडी का बोझ बढ़ सकता है। अगर चुनावी मजबूरी के कारण इन उत्पादों की खुदरा कीमत नहीं बढ़ने दी गई तो सरकार का राजकोषीय घाटा बढ़ सकता है। इस साल के अंत में चार अहम राज्यों में चुनाव होने हैं और फिर अगले साल आम चुनाव होंगे। कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के प्रभाव को कम करने के लिए वित्त मंत्री पर पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में कटौती करने का भी दबाव होगा। प्रति लीटर पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में एक रुपये की कमी से सरकार के राजस्व में कम से कम 260 अरब रुपये की कमी आएगी। जेटली ने राजकोषीय घाटे को जीडीपी का 3.3 फीसदी रखने का लक्ष्य रखा है लेकिन उत्पाद शुल्क में कटौती से इन लक्ष्य को हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। विनिवेश से होने वाली कमाई तथा लाभांश और मुनाफे से आने वाला गैर कर राजस्व भी इसी तरह की चुनौतियां पेश करेंगे। जुलाई के अंत तक सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अपनी हिस्सेदारी के विनिवेश से केवल 92 अरब रुपये ही जुटा सकी जबकि इसके लिए सालाना लक्ष्य 800 अरब रुपये निर्धारित किया गया है। एयर इंडिया के निजीकरण की योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, इसलिए सरकार के लिए यह

लक्ष्य हासिल करना मुश्किल है। सार्वजनिक क्षेत्र के कई उपक्रमों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है और यहां तक कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (सेल) ने भी इस वर्ष कोई लाभांश नहीं देने की घोषणा की है। ऐसी स्थिति में लाभांश और मुनाफे से 1.07 लाख करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य हासिल करना भी मुश्किल लग रहा है। राजकोषीय समेकन के मोर्चे पर सरकार को अच्छी खबर केवल वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था से ही मिली है। इसका कारण जीएसटी संग्रह नहीं है जिसकी विकास दर अब भी कमजोर है। जेटली को राजस्व लक्ष्य हासिल करने में जीएसटी बर्यों मददगार होगा, इसका कारण जीएसटी मुआवजा उपकर से संबंधित कानून में किया गया एक संशोधन है। पिछले महीने की शुरुआत में सरकार ने जीएसटी मुआवजा उपकर से संबंधित विशेष कानून में संशोधन किया था। इससे सरकार को अधिशेष संग्रह को भारत की समेकित निधि में रखने और राज्यों के साथ 50:50 के अनुपात में साझा करने के बाद मौजूदा वर्ष में ही इसके इस्तेमाल की अनुमति मिल गई। पहले यह प्रावधान था कि मुआवजा उपकर अधिशेष को सरकारी खाते में रखा जाना चाहिए और 2022 से पहले इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहें तो सरकार और राज्य 2022 तक इंतजार करने के बजाय अब उपकर अधिशेष का इस्तेमाल 2018-19 में ही कर सकते हैं। यह जेटली के लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। जीएसटी के जुलाई 2017 से मई 2018 तक के आंकड़ों के मुताबिक करीब 40 फीसदी उपकर अधिशेष है। जुलाई 2017 से मार्च 2019 तक कुल 1.51 लाख करोड़ जीएसटी मुआवजा उपकर संग्रहीत होने का अनुमान है। इस तरह केंद्र और राज्य इस वित्त वर्ष के दौरान करीब 600 अरब रुपये अधिशेष साझा कर सकेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो जेटली के पास जीएसटी संग्रह में कमी की चिंता करने के बजाय 300 अरब रुपये की गुंजाइश होगी।

बढ़ती कारों का काफिला रोक कर ही बढ़ेगी हमारी रपतार

आज का राशीफल

आज का राशीफल	
मे़ष	कार्यक्षेत्र में रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। रुका हुआ कार्य सम्पन्न होगा। पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। वाहन प्रयोग में सावधानी अपेक्षित है।
वृषभ	आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। अनावश्यक कष्ट का सामना करना पड़ेगा। बाणी की सौम्यता आपको प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगी। धन लाभ के योग हैं। वाद-विवाद की स्थिति आपके हित में न होगी।
मिथुन	बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। आय के नवीन स्रोत बनेंगे। मन प्रसन्न होगा। जारी प्रयास सार्थक होंगे। किसी अभिन्न मित्र से मिलाप होगा। प्रणय संबंध मधुर होंगे। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय न लें।
कर्क	राजनैतिक महात्माकांक्षा की पूर्ति होगी। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। व्यावसायिक योजना सफल होगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। आय और व्यय में संतुलन बनाकर रहें।
सिंह	पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। यात्रा में अपने सामान के प्रति सचेत रहें चोरी या खोने की आशंका है। बाणी की सौम्यता आपको प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगी। व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी।
कन्या	पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। संज्ञा के दायित्व की पूर्ति होगी। मांगलिक कार्य में हिस्सेदारी होगी। प्रणय संबंध प्रगाढ़ होंगे। मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे।
तुला	व्यावसायिक योजना फलीभूत होगी। बाणी की सौम्यता से आपको प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। किसी अभिन्न मित्र से मिलाप की संभावना है। व्यर्थ की उलझनें रहेंगी।
वृश्चिक	आर्थिक योजना को बल मिलेगा। भाई या पड़ोसी का सहयोग मिलेगा। अनावश्यक व्यय का सामना करना पड़ेगा। यात्रा देशांतर की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा।
धनु	गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। राजनैतिक दिशा में किए जा रहे प्रयास सफल होंगे। ईश्वर के प्रति आस्था बढ़ेगी।
मकर	जीविका की दिशा में उन्नति होगी। किसी अभिन्न मित्र से मिलाप होगा। बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। व्यावसायिक सफलता मिलेगी। ससुराल पक्ष से लाभ होगा। धन हानि की संभावना है।
कुम्भ	पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय न लें। पिता या उच्चाधिकारी से वताव मिलेगा। आय और व्यय में संतुलन बनाकर रहें। बाणी पर निश्चय रहें।
मीन	व्यावसायिक योजना फलीभूत होगी। भाग्यवश कुछ ऐसा होगा जिसका आपको लाभ मिलेगा। आय के नए स्रोत बनेंगे। जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। वाहन प्रयोग में सावधानी अपेक्षित है।

विवार मंथन

जयतीलाल भंडारी, अर्थशास्त्री

इन दिनों दुनिया भर में भारत के शहरों में बढ़ती हुई कारों से बढ़ते हुए पेट्रोल-डीजल के उपभोग, बढ़ते टैफिक जाम और बढ़ते प्रदूषण पर लगातार अध्ययन और रिपोर्ट प्रकाशित हो रही हैं। नीति आयोग ने भी इसे लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें ज्यादा प्रदूषित शहरों में निजी कारों के इस्तेमाल पर उपयोग सरचार्ज यानी कंजेशन शुल्क लगाने की सिफारिश की गई है। आयोग को उम्मीद है कि इससे निजी वाहनों का इस्तेमाल कम होगा और प्रदूषण घटेगा। विश्व बैंक की

नई रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के शहर कारों की बढ़ती संख्या से पैदा हो रही परेशानियों से निपट पाने में सक्षम नहीं हैं। दूसरी तरफ विश्व स्वास्थ्य संगठन एक एक रिपोर्ट के मुताबिक, कानपुर, फरीदाबाद, गया, वाराणसी, पटना, दिल्ली, लखनऊ, आगरा, गुरुग्राम व मुजफ्फरपुर भारत के 10 सबसे प्रदूषित शहर हैं। यहां प्रदूषणजन्य बीमारियां लगातार बढ़ रही हैं। विज्ञान एवं पर्यावरण मंत्रालय से संबंध संसदीय समिति के अनुसार, दिल्ली में शहरीकरण और बढ़ते वाहनों के प्रदूषण से 2013 से 2017 के बीच 17 लाख लोग सांस की बीमारी के

शिकार हुए हैं। इस समय दुनिया के विकासशील देशों में सबसे अधिक कारें भारत में हैं। जुलाई 2018 के अंत में देश की सड़कों पर लगभग ढाई करोड़ कारें दौड़ रही थीं। देश में प्रतिमाह करीब दो लाख से अधिक कारों की बिक्री हो रही है। देश में जहां कारों का ढेर लगता जा रहा है, वहीं देश में बसों की संख्या बहुत कम है। देश में करीब 19 लाख 70 हजार बसें हैं। इनमें से 18 लाख 30 हजार निजी क्षेत्र में और 1 लाख 40 हजार सरकारी क्षेत्र में हैं। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के आकलन के अनुसार, छोटी कारों की कम कीमत

तथा सरलता से उपलब्ध बैंक लोन के कारण दोपहिया से उठकर चार पहिया वाहन की सवारी करने के इच्छुक लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। हालत यह है कि इसके कारण सड़कें अवसर जाम रहती हैं और पार्किंग में अमती पर लक्ष्य नहीं मिलती। अब हमें तय करना है कि हम वर्तमान पीढ़ी को कैसा पर्यावरण देना चाहते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कैसी विरासत छोड़ते हैं। स्पष्ट है कि कारें भारतीय सामाजिक जीवन का भविष्य नहीं हो सकती हैं। इसलिए देश के सभी शहरों में सार्वजनिक परिवहन की कारगर व्यवस्था पर विचार मंथन

जरूरी है। इस समय देश में पांच हजार छोटे-बड़े शहरों में से एक प्रतिशत शहरों में भी सार्वजनिक परिवहन की भरोसेमंद और पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। शहरी यातायात नियोजन विभाग की एक रिपोर्ट के अनुरूप हमारे देश में दिल्ली और बंगलुरु के 27 फीसदी कामकाजी और लखनऊ के केवल 11 फीसदी कामकाजी लोग ही काम पर जाने के लिए सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करते हैं, जबकि दुनिया के अधिकांश विकसित और विकासशील देशों में सार्वजनिक परिवहन प्रणाली से आने-जाने वालों की संख्या इससे कहीं

ज्यादा है। लंदन में 45 फीसदी और सिंगापुर में 59 फीसदी लोग सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का ही उपयोग करते हैं। हम सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था की बेहतरी और प्रदूषण से मुक्ति के लिए दुनिया के कई बड़े शहरों से सबक ले सकते हैं। लंदन में इसके लिए 2003 से कारों पर कंजेशन चार्ज लगाने की शुरुआत हुई और अब वहां हर कार पर प्रतिदिन 1,025 रुपये चुकाने पड़ते हैं। स्वीडन के स्टॉकहोम, इटली के मिलान तथा सिंगापुर में भी कंजेशन चार्ज लगता है। हमारे देश में, खासतौर से प्रदूषित एवं टैफिक जाम से बेहाल शहरों में

सड़कों पर चलने वाली निजी कारों पर कर वसूला जाना चाहिए। नीति आयोग ने भी यही कहा है कि ऐसे विकल्पों पर तुरंत काम करना शुरू कर दिया जाना चाहिए, ताकि देश भर में वर्ष 2022 तक ज्यादा प्रदूषण वाले शहरों में हर जगह पहुंच चकने वाला इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट शुरू किया जा सके। हालांकि पूरे देश में इसकी शुरुआत इतनी आसान नहीं है। नीति आयोग की सिफारिशों को जमीन पर उतारने के लिए जिस इच्छाशक्ति की जरूरत है, वह फिलहाल कहीं दिख नहीं रही। न इस पर बहुत चर्चा ही हो रही है। (ये लेखक के अपने विचार हैं)



सूरत । डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक के वाइस चेयरमैन के पद पर फिर से संदीप भाई देसाई की नियुक्ती होने पर सचिन बाजार संगठन की और से संदीप भाई देसाई बधाई और शुभेच्छा स्वरुप फुलों का गुलदस्ता देते हुए ।

हार्दिक पटेल उपवास : आज कांग्रेस कार्यकर्ता उपवास पर

अहमदाबाद । हार्दिक पटेल के अनिश्चितकालीन उपवास और किसानों के प्रश्न लड़ने के मूड में आ गये कांग्रेस ने गुरुवार को मुख्यमंत्री विजय रुपाणी से मिलकर आवेदनपत्र सौंपा गया । कांग्रेस ने स्पष्ट मांग की है कि, राज्य सरकार संवेदनशीलता और अहंकार छोड़कर हार्दिक के साथ सीधा बातचीत करे । गुरुवार को वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अर्जुन मोढवाडिया, सिद्धार्थ पटेल के अलावा विपक्ष के नेता परेश धानाणी तथा विधायकों सहित कांग्रेस के एक प्रतिनिधि ने गुरुवार को शाम में मुख्यमंत्री ऑफिस में विजय रुपाणी से मुलाकात की

और किसान हार्दिक पटेल के उपवास आंदोलन मामले में इसके साथ सीधा बातचीत करे, किसानों की कर्ज माफी, अल्पेश कथीरिया सहित के प्रदर्शनकारियों की मुक्ति और राज्य में प्रजातंत्र मूल्यों को बनाये रखने की मांग की । इसके साथ कांग्रेस ने राज्य सरकार को २४ घंटे का अल्टीमेटम दिया गया हालांकि सरकार यह पूरे मामले में २४ घंटे में निर्णय नहीं ले तो शुक्रवार को सुबह में ११ बजे से शनिवार को ११ बजे तक राज्य के सभी जिलों-तहसीलों पर उपवास, विरोध और प्रदर्शनों के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे । हार्दिक पटेल का उपवास आंदोलन जबकि

१३वां दिन है तब कांग्रेस ने अब इस मामले में सीधा हस्तक्षेप किया है । कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को सीएम रुपाणी की मुलाकात लेकर उनको अब हार्दिक के उपवास आंदोलन मामले में हार्दिक के साथ बातचीत करने के लिए तथा किसानों के हित में कदम उठाने की कार्रवाई की थी । इतना ही नहीं, यह मामले में राज्य सरकार २४ घंटे में कदम नहीं उठायेगी तो शुक्रवार को सुबह में ११ बजे से शनिवार को सुबह में ११ बजे तक राज्य के सभी जिलों-तहसीलों में कांग्रेस के कार्यकर्ता उपवास आंदोलन करेंगे और विरोध व्यक्त करेंगे ।

हार्दिक ने अनिश्चितकालीन उपवास 13 वें दिन जारी

24 घंटे के अल्टीमेटम की अवधि पूरी होने पर हार्दिक ने जल भी त्यागा



अहमदाबाद । पाटीदार समुदाय के लिए आरक्षण और किसानों के लिए कर्ज माफी की मांग के साथ अनिश्चितकालीन उपवास पर बैठे हार्दिक पटेल की तबियत एक तरफ ज्यादा

बिगड़ रही है । हार्दिक पटेल के अनिश्चितकालीन उपवास में गुरुवार को १३वें दिन भी आरोप-प्रतिआरोप का दौर जारी रहा । दूसरी तरफ बातचीत के लिए अल्टीमेटम देने के बाद २४ घंटे

की अवधि पूरी होने के बाद हार्दिक पटेल ने फिर से जल त्याग कर दिया । इस संदर्भ में हार्दिक पटेल की तरफ से और पास के नेता मनोज पनारा ने बात की । मनोज ने बताया है कि, सरकार को इस मामले में गंभीरता नहीं दिखाई दे रही है । बातचीत के लिए सरकार उत्सुक नहीं है । सरकार पर हमला करते हुए पनारा ने कहा है कि, यूपी में कर्ज माफी हो सकता है तो गुजरात में क्यों नहीं हो सकता है । मनोज ने यह भी कहा है कि, जहां तक हमारी मांग को स्वीकार नहीं किया जाएगा वहां तक

हम दृढ़ता के साथ आगे बढ़ेंगे । उन्होंने यह भी कहा है कि, खोडलधाम ट्रस्ट के चेयरमैन नरेश पटेल का हम सम्मान करते है यदि वह मध्यस्थता बनकर पेशकश करेंगे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है । पास के कन्वीनर हार्दिक पटेल के अनिश्चितकालीन उपवास के १३वें दिन इनकी तबियत ज्यादा बिगड़ गई थी । हार्दिक को कमजोरी, बेबसी सहित बिगड़े स्वास्थ्य के बीच स्वास्थ्य के खतरे का सामना कर रहे है । पिछले १३ दिन के उपवास को लेकर कमजोरी के कारण हार्दिक

अब चलने में असमर्थ बन गये और इसे गुरुवार को सुबह से ल्हीलचेयर पर बिठाकर उपवास छावनी तक ले जाना पड़ा । दूसरी तरफ हार्दिक पटेल ने गुरुवार शाम तक में यदि सरकार इसके साथ सीधी बातचीत नहीं करे तो वह जल त्याग की चेतावनी दी गई होने से पूरे पाटीदार समाज में काफी उत्तेजना माहौल छाया है । शाम को हार्दिक की तबियत ज्यादा बिगड़ने पर वह आंखों पर रुमाल रखकर सो गईं देखने को मिले, उनमें बात करना या आंख खुला रखकर हमेशा देखने की शक्ति भी कम होती जा रही है ।



सूरत । हिन्दु मुस्लिम एकता के प्रतीक सूफी संत के मजार पर रंग बिरंगी लाईट लगा कर सजावट की गई । ये प्रोग्राम लगातार 25 वर्ष से किया जा रहा है ।

सूर्यनगरी एक्सप्रेस से सोने के पैकेट के साथ कुरियर बॉय गिरफ्तार!

टीटीइ ने युवक को स्लीपर कोच में जनरल टिकट लेकर यात्रा करते हुए पकड़ा ट्रेन स्कॉटिंग पार्टी ने सूरत लाने के बाद युवक को दोबारा बोरीवली भेजा

सूरत. बान्द्रा टर्मिनस-जोधपुर सूर्यनगरी एक्सप्रेस में गुरुवार को रेलवे सुरक्षा बल की ट्रेन स्कॉटिंग पार्टी ने एक कुरियर बॉय को बोरीवली स्टेशन पर सोने के पैकेट के साथ गिरफ्तार किया है । हालांकि सोने का वजन और कीमत सार्वजनिक नहीं की गई है । चर्चा है कि सत्रह करोड़ का सोना पकड़ा गया है ।

बान्द्रा टर्मिनस से प्रतिदिन 12480 बान्द्रा टर्मिनस-जोधपुर सूर्यनगरी एक्सप्रेस दोपहर 1.30 रवाना होती है । इसमें रेलवे सुरक्षा बल के जवानों की ड्यूटी ट्रेन स्कॉटिंग पार्टी के तौर पर लगाई जाती है । सूर्यनगरी एक्सप्रेस के बोरीवली पहुंचने पर ट्रेन के टीटीई ने एक युवक को द्वितीय श्रेणी शयनयान कोच में जनरल टिकट लेकर यात्रा करते हुए पकड़ा । टीटीई ने उसे संदिग्ध मानते हुए ट्रेन स्कॉटिंग पार्टी को सौंप दिया ।

रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने उससे पूछताछ की तो उसने अपना नाम मनीष कुमार बनवारीलाल सिंह (21) बताया । वह मूल रूप से राजस्थान के झुंझनू जिले का निवासी है और हाल में मुम्बई में रहता है और एयर पार्सल नामक कुरियर कंपनी में नौकरी करता है । वह नियमित मुम्बई से सूरत के लिए पार्सल लेकर ट्रेन में आता था । पूछताछ करने पर मनीष ने पार्सल के पैकेट में सोना होने की जानकारी दी, लेकिन मनीष ने पैकेट खोलने



से इनकार किया । उसने रेलवे सुरक्षा बल को बताया कि उसके कुरियर के मालिक के सामने वह पैकेट खोल देगा ।

इसके बाद रेलवे सुरक्षा बल की स्कॉटिंग पार्टी उसे सूरत लेकर पहुंची । सूरत स्टेशन पर रेलवे सुरक्षा बल के जवान मनीष को लेकर रेलवे पुलिस थाने पहुंचे । बाद में मनीष को बोरीवली में पकड़े जाने के कारण मामला वहीं रफ्तार कर उसे जवानों के साथ बोरीवली रवाना कर दिया गया । पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पैकेट में सोना है, लेकिन सोने का वजन और कीमत के बारे में कोई जानकारी नहीं है । सत्रह करोड़ का सोना पकड़े जाने की सिर्फ चर्चा है ।

साधना-आराधना का चला दौर

सूरत. जैन धर्म के पर्वधिराज पर्युषण महापर्व के पहले दिन गुरुवार को जैन धर्मावलम्बियों में भारी उत्साह देखने को मिला । चार सम्प्रदायों में से श्वेताम्बर मूर्तिपूजक व स्थानकवासी संघ के पर्युषण महापर्व की शुरुआत में सुबह से जिनालयों में जिनेश्वर प्रभु की पूजा व दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की कतार लगी । वहीं, विभिन्न क्षेत्रों में गुरु भगवंतों के सान्निध्य में आयोजित प्रवचन के दौरान सैकड़ों की संख्या में श्रावक-श्राविकाओं ने जिनवाणी का श्रवण लाभ लिया । पर्युषण महापर्व के पहले दिन गुरुवार को सुबह प्रवचन के दौर



के बाद शाम को प्रतिक्रमण व रात्रि में भजन संध्या के आयोजन किए गए । इसके अलावा प्रभु पूजा, आंगी रोशनी, स्नात्र महोत्सव, महापूजा, सामायिक, प्रतिक्रमण, पौषध व तपस्या के दौर भी गुरुवार से शुरू हो गए । उधर, तेरापंथ संघ का पर्युषण महापर्व शुक्रवार से शुरू होगा और इस दौरान सिटीलाइट,

उधना, परवत पाटिया के तेरापंथ भवनों में साध्वीवृंद के सान्निध्य में प्रवचन समेत अन्य धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे । वहीं, टीकमनगर जैन संघ उपाश्रय में पन्यास पंचदर्शन विजय महाराज ने पर्युषण महापर्व के बारे में श्रद्धालुओं को सुबह प्रवचन में अहिंसा, साधर्मिक भक्ति, क्षमा एवं अनुकंपा दान

के अलावा व्यक्ति के पांच कर्तव्यों को जीवन में अहम बताया । रांदेर रोड पर निशान फलिया जैन संघ

में विराजित ज्ञानरश्मिविजय महाराज के सान्निध्य में महापर्व की शुरुआत में गजलक्ष्मी अनुष्ठान करवाया गया । इसके बाद पर्युषण पर्व पर प्रवचन हुआ और संघ पूजा का आयोजन किया गया ।

महादेव मीडिया

रोहताश यादव 9924144499, 7015339195

वीजिटिंग कार्ड, बिल बुक, लेटर पैड, बेनर, पोस्टर, आदि का डिजाइन बनवाने के लिए संपर्क करें। (हिन्दी, गुजराती)

हिन्दी, गुजराती न्युज पेपर डिजाइन करवाने के लिए संपर्क करें।

304 केवल कॉम्पलेक्ष नवा गाम, डिंडोली, उधना सूरत ।

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ऑफसेट एफपी. 149, प्लोट 26 खोडियार नगर, सिद्धीविनायक मंदिर के पास, (भाटेना) हॉ.सो. अंजना सूरत, गुजरात से मुद्रित, एवं 191 महादेव नगर, हरि नगर-2 के पीछे, उधना, जिला-सूरत, गुजरात से प्रकाशित, **संपादक :- सुरेश मौर्या** फोन नं. (9879141480) **RNI.No. : GUJHIN/2018/75100**, E-mail: krantisamay@gmail.com